n Indian Industries Association Publication

king.....

DIA FOOD EXPO -2004

Special

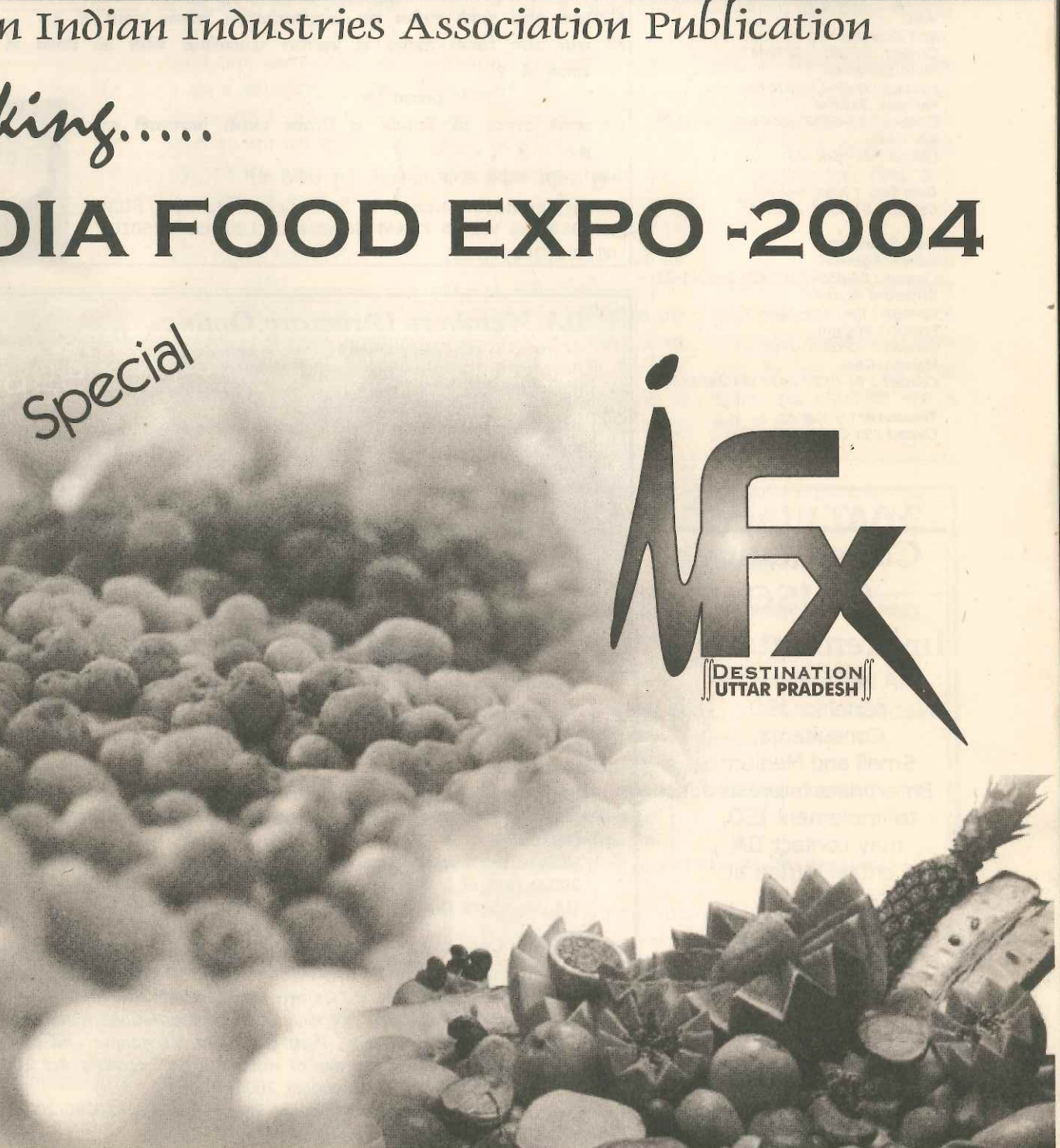

INDIA FOOD EXPO 2004 PHOTO GALLERY

A Glimpse of India Food Expo Inaugural...

Minster Small Scale Industries, Government of UP. Shri Jagdish Singh Rana cutting the ribbon of India Food Expo - 2004 (left), lighting the lamp in the presence of IIA President Shri G.C Chaturvedi (right), Addressing the Inaugural (below)

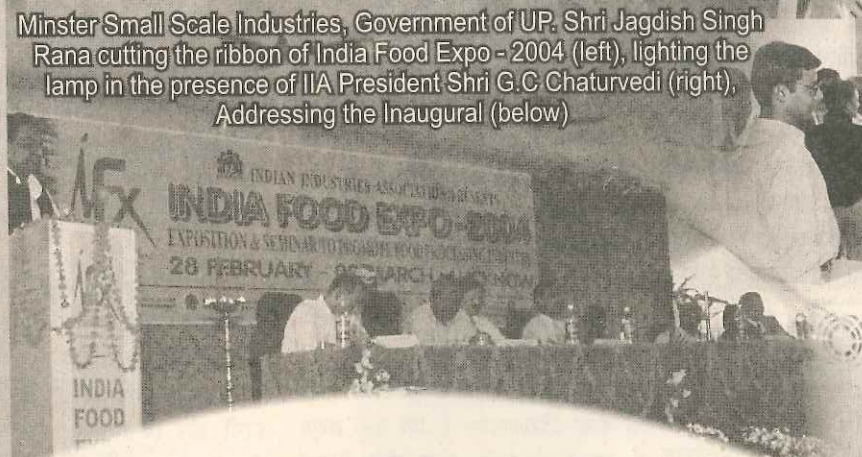

Shri Rana Visiting the Stalls at the Expo

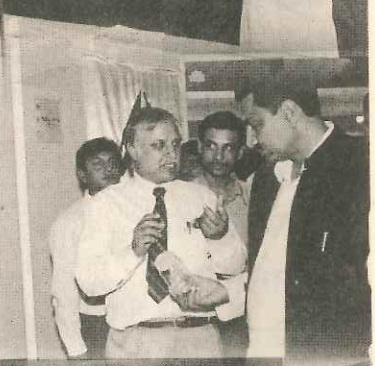

Indian Food Expo -2004
the Assortment of Stalls

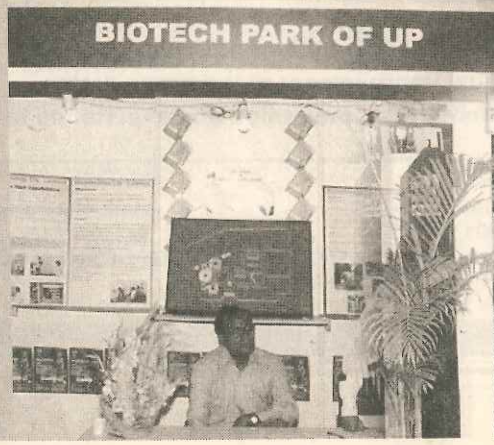

इण्डिया फूड एक्सपो - २००४ के उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन श्री जी०सी० चतुर्वेदी के भाषण के अंश

आदरणीय जगदीश सिंह राणा जी, मंचासीन अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों एवं साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन होगा जब प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित सबसे बड़ा आयोजन इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन{आई०आई०ए०} प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से प्रारम्भ किया जा रहा है। सदियों से कृि का प्रदेश के आर्थिक मानचित्र पर गहरा प्रभाव रहा है। प्रदेश के कुल घरेलू उत्पाद का ४५ प्रतिशत हिस्सा कृि पर आधारित है। देश का १६ प्रतिशत अन्न उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इसके विपरीत प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिहाज से प्रदेश में अब तक बहुत कम प्रगति हुई है फिर भी आज लगभग ३४०० छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ प्रदेश में स्थित है जिनमें लगभग ३.४० लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों में कुल पूँजी निवेश लगभग २१०० करोड़ रूपये का है। अन्तर्रा ट्रीय प्रतिस्पर्धा के आने तथा ट्रेड वैरियर ढीले होने से भारत जैसे कृि प्रधान देश के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रगति करने का एक सुनहरा मौका सामने खड़ा है। एक अनुमान के अनुसार आने वाले दस सालों में देश में लगभग १,४०,००० करोड़ रूपये तथा प्रदेश में लगभग १०,००० करोड़ रूपये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश होने की संभावना है जिससे देश में कृि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग ५० लाख बेरोजगार व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त होगा।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन विगत एक वर्ा से कृि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत हैं। इस हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का एक अलग वर्किंग ग्रुप गठित किया गया है। उद्यमियों की सहायता के लिए आई०आई०ए० में सिडबी की सहायता से स्थापित लघु उद्योग सूचना सेवा केन्द्र द्वारा सभी प्रकार की सूचनॉए प्रदान की जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों मे अपार सम्भावनाओ को देखते हुए आई०आई०ए० ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से सम्बन्धित एक अलग नीति बनाई जाए इसके लिए आई०आई०ए० द्वारा प्रदेश सरकार को सुझाव भी भेज दिये है जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है:-

- सभी प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को २४ घण्टे विद्युत आपूर्ति चाहे ये उद्योग कही भी स्थापित हो।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कॉन्ट्रेक्ट फारमिंग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाए।
- वर्तमान में भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु बहुत लम्बा समय लग जाता है इसके लिए अधिकतम ३ महीने का समय निर्धारित होना चाहिए।
- पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज एवं सप्लाई चेन की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- परीक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को औद्योगिक संघो व उद्यमियों के साथ जौइन्ट सेक्टर के रूप में चलाना।
- रूरल रिजनल बैकों द्वारा कम से कम २५ प्रतिशत ऋण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पीएलआर से २ प्रतिशत कम व्याज पर सुनिश्चित किया जाए।
- गुणवत्ता एवं पेटेन्ट हेतु प्रोत्साहन योजनाऍ बनाई जाए।
- मण्डी टैक्स की बाध्यता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर से हटा ली जाये।
- ब्राण्ड इमेज स्थापित करने तथा विपणन सहायता योजनाये बनाई जाये।
- आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विभिन्न प्रकार के लगभग २५ कानून एवं औपचारिकतॉए लागू है इन्हे अविलम्ब कम करने की आवश्यकता है तथा केवल एक फूड कानून बनना चाहिए।

मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्दी ही प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अलग नीति घोषित करेगी।

मकुछ मुख्य प्रावधान जो प्रदेश में औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है और औद्योगिक नीति मे नही है वे इस प्रकार है:-

- लगातार विद्युत सप्लाई का प्रावधान केवल १३२ केवी से जुड़े औद्योगिक आस्थानों के लिए किया गया है। जबकि प्रदेश में ८० प्रतिशत से अधिक उद्योग ११ केवी/३३केवी फीडरो से पोिात है इन उद्योगों को भी लगातार विद्युत सप्लाई का प्राविधान अनिवार्य है।
- नई औद्योगिक नीति प्राविधानों से भी पड़ोसी राज्य उत्तरांचल में प्राप्त छूटों की बराबरी नही हो रही है। अतः इस ओर भी प्रयास करने की आवश्यकता है। खासतौर पर प्रदेश में पहले से स्थापित उद्योगों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहॉ यह भी कहना उचित होगा कि नये उद्योग प्रदेश में तभी लगेगे जब उन्हे पुराने उद्योग स्वस्थ दिखाई देगे।
- प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा प्रदेश के बाहर से उत्तरांचल के उद्योगों से सामान कय किया जा रहा है क्योंकि वहॉ विभिन्न प्रकार की कर राहत उपलब्ध होने के कारण सामान की कीमत कम बैठ रही है। अतःउत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश में स्थित उद्योगों को वरियता प्रदान करने का प्रावधान करने के बारे नीति निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- प्रदेश के उद्यमियों को फार्म ३-ख के विरूद्ध कच्चा माल खरीदने पर २ से ५ प्रतिशत टैक्स देय है हमारा अनुरोध है कि प्रदेश के उद्यमियो को भी फार्म ३ ख के विरूद्ध कच्चे माल की खरीद पर शून्य टैक्स देय होना चाहिए।
- अभी हाल ही में घोषित विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में २५ करोड़ {पूर्वाचंल तथा बुन्देलखण्ड में १० करोड़ तक} के उद्योग स्थापित करने पर व्यापार कर की स्कीम को लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारा सरकार से अनुरोध है कि निवेश की सीमा समाप्त होनी चाहिए जिससे लघु उद्योगो को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। दस साल तक व्यापार कर, विभाग में न जमा कराते हुए १० साल के पश्चात जमा कराये गये धनराशि पर प्रतिवर्ा के अनुसार व्यापार कर का भुगतान करने की अनुमति होनी चाहिए। इस नीति से जहॉ एक ओर नई इकाईयों को प्रोत्साहन मिलेगा वही दूसरी ओर पुराने उद्योगों पर भी इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।
- प्रदेश में प्लास्टिक उद्योग सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभर रहा है लेकिन प्लॉस्टिक के उत्पादों पर १० प्रतिशत व्यापार कर देय होने के कारण प्रदेश में बिना बिल के माल बेचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है अतः यदि प्लास्टिक प्रोडक्टस के ऊपर ४ प्रतिशत व्यापार कर कर दिया जाये तो यह उद्योग प्रदेश में और पनपेगा जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।
- हमारे पड़ोसी दिल्ली प्रदेश में लेटेस्ट रबर फोम पर ८ प्रतिशत व्यापार कर देय है जबकि हमारे प्रदेश में १६ प्रतिशत कर देय है। जिसके कारण हमारे प्रदेश के उद्योग अपने पड़ोसी प्रदेश से प्रतिस्पर्धा नही कर पा रहे है और बन्दी की ओर अग्रसर है अतः हमारा सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश में भी लेटेस्ट रबर फोम पर व्यापार कर ८ प्रतिशत कराया जाये।

मुझे आशा है कि प्रदेश सरकार उपरोक्त सुझावो को क्रियान्वित करने की ओर तीव्रता से कदम उठाएगी।

Speakers at the Seminar...

Mr Ravindra, IAS
Special Secretary Idustrial Dev. UP
& Jt. Executive Director Udyog Bandhu

Shri Namgial
GM SIDBI

Shri N.P Saha
Joint Director
IIP

Mr Sanjeev Asthana
Cargill

Mr Vijay Sardana
Director Center for Int. Trade in
Agriculture & Agri based Industries

hri. A.N.P Sinha
oint Sec. MoFPI,
Govt of India

Dr, V.P. Sharma
IITRC

Mr I C Shukla
CFTRI

Shri. P.K Sethi
CEO, Biotech Park

Shri Rajnish Sethi
Chairman,
Food Processing Working Group, IIA

Delegates at the Seminar

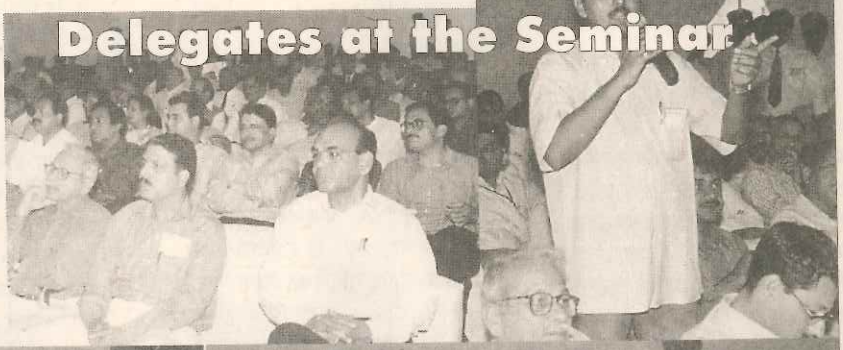

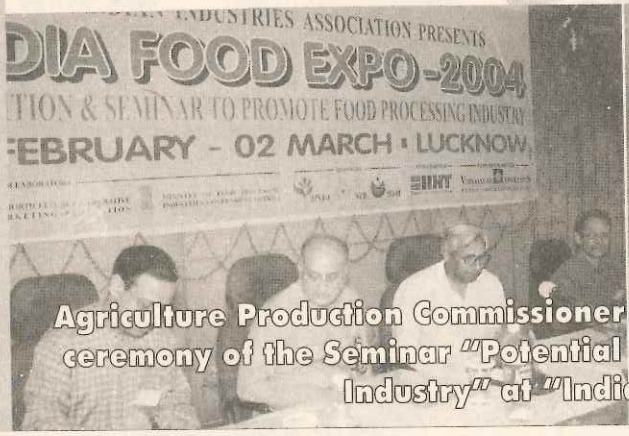

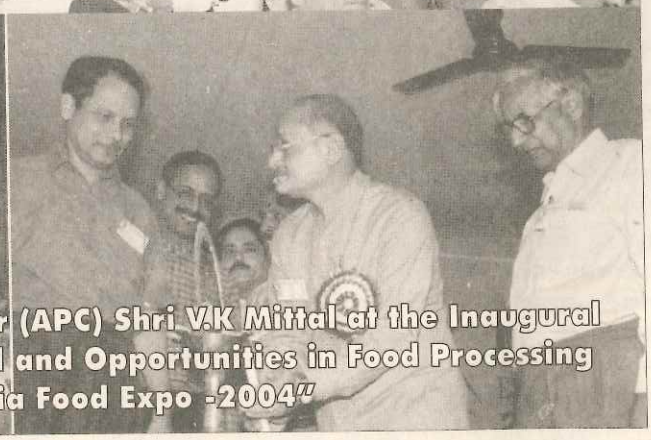

Agriculture Production Commissioner (APC) Shri V.K Mittal at the Inaugural ceremony of the Seminar "Potential and Opportunities in Food Processing Industry" at "India Food Expo -2004"

इण्डिया फूड एक्स्पो– 2004 का सफल आयोजन

इण्डिया फूड एक्स्पो – २००४ का उद्घाटन २८ फरवरी २००४ को प्रदेश के उद्योग मंत्री माननीय जगदीश सिंह राणा जी ने किया उन्होने प्रदर्शनी का पूरा अवलोकन किया व उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की नितान्त आवश्कता है जिसके लिए उद्यमियों का आवहन करते हुए उन्होने राजकीय सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।

इस अवसर पर आई०आई०ए० अध्यक्ष श्री गणेश चतुर्वेदी जी ने सबका स्वागत किया। आयोजन के अध्यक्ष श्री रजनीश सेठी ने आयोजन की महत्ता पर विचार रखा और बताया कि अपना प्रदेश कई फसलों में प्रथम स्थान पर है लेकिन खाद्य प्रसंस्करण बहुत कम हो रहा है। प्रदेश के किसानों की फसल का बहुत बड़ा हिस्सा भण्डारण व प्रसंस्करण उद्योग न होने से बेकार हो जाता है किसानों को भी सही मूल्य नही मिल पाता है व उपभोक्ता को भी संतुष्टि नही मिल पाती है।

प्रदेश के सचिव उद्यान श्री अनिल स्वरूप जी ने इस आयोजन की उपयुक्त्ता पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के आंवले, केले, शहद, आलू, आम आदि की मानकीकरण और प्रसंस्करण के लिए काफी योजनाये बनाई है। इस प्रदर्शनी मेले में ७२ स्टाल लगे है जिनमें लघु व मध्यम वगे के ४६ स्टाल थे। बड़े उद्योग के ७ स्टाल थै पैकेंजिग उद्योग के २ थे, मशीनरी उद्योग के ३, सरकारी विभागो के, केन्द्र सरकार के ८ व प्रदेश सरकार के १२ स्टाल थे। मेले में चारो दिन आने वाले दर्शकों की अच्छी संख्या तरकरीबन २५००० रही है जिनमें सम्भावित उद्यमी वर्ग व उपभोक्ता वर्ग शामिल हैं।

प्रदर्शनी के साथ दो दिन की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया जिसका उद्घाटन कल १ मार्च को प्रदेश के कृषि उत्पाद आयुक्त श्री वी०के० मित्तल जी ने किया एवं इसके विशिष्ठ अतिथि दिल्ली से आये श्री ए० एन० पी सिन्हा जी थे जो कि केन्द्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में सयुक्त सचिव के पद पर हैं। १ मार्च को दो तकनीकी सत्र हुए जिसमें प्रथम सत्र इन्वेस्टर प्राइड के अध्यक्ष श्री एएनपी सिन्हा जी थे व द्वितीय सत्र इन्टरप्रन्योर डिलाइट के श्री अनिल स्वरूप जी थे। इसमे बड़े उद्योगो से कारगिल व आईटीसी का प्रजेन्टेशन हुआ। इन दोनेा संस्थाओं ने बताया कि इनकी योजनाये गाँव–गाँव में किसानों के हित का ध्यान रख रही है। जहाँ आईटीसी ने ई–चौपाल से किसानो में जागरूकता व इन्टरनेट के जरिये सीधे देश की मन्डियों से जोड़ने की बात बताई, वही कारगिल ने किसानो के फसल का सही परीक्षण व अच्छी गुणवत्ता के फसल को उच्च मूल्य देने की बात बताई। द्वितीय सत्र में डा०पी०के०सेठ मुख्य कार्यकारी जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक)पार्क ने खाद्य प्रसस्करण में जैव प्रोद्योगिकी(बायोटेक)के प्रयास से होने वाली उन्नति के विषय पर बताया।

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० के श्री आलोक कुमार,ने बताया कि प्रदेश सरकार ने चार जगह कृषि पार्क बनाने की योजना है जिसमें लखनऊ वाराणसी में निमार्ण कार्य चल रहा है व भूमि हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जा रहे है तथा १४/३/०४ तक लखनऊ के लिए प्रार्थना पत्र देने वालो को १० प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध है । दो अन्य स्थान चोला व सहारनपुर के लिए पार्क प्रस्तावित है। उद्योग बन्धु के संयुक्त निदेशक श्री रवीन्द्र जी ने प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के प्रमुख अंश बताते हुए कहा कि इसमें उद्योगों की पहले की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है एवं इंस्पेक्टर राज पर अंकुश लगाने की चेष्टा की गई है।

नाबार्ड के श्री देसाई ने बताया कि उनकी संस्था कृषि उत्पाद से लेकर उपभोक्ता तक के लिए विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान कर रही है विशेषकर भण्डारण शीतग्रह व कान्ट्रेक्ट फार्मिग हेतु भी विशे। पैकेज एग्रो एक्सपोर्ट जोन हेतु दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के श्री त्रिपाठी जी ने बताया कि उनका विभाग केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करा रहा है जो कि फल सब्जी के सम्बन्ध रखती है। इसमें व्यापारिक आधार के फल सब्जी के पैदावार व बाद की प्रबन्धन व विपणन व्यवस्था,शीतगृह व भण्डारण गृह हेतु केन्द्रीय पूंजीगत सहायता, तकनीकी सुधार हस्तांतरण सहायता,बाजार सूचना सहायता व अन्य सर्वेक्षण परामर्श सहायता प्रदान होती हैं।

दोनो सत्र के अन्त में जिज्ञासा प्रश्न के लिए समय रखा गया जिसमें बहुत उत्साह से उद्यमियों व गॉव के खेती से जुड़े वर्ग ने प्रश्न पूछ कर समाधान प्राप्त किया। प्रश्नों की बौछार से लगता था कि तकनीकी सत्र के श्रोतागण बहुत ध्यान से बताई जा रही है जानकारियॉ सुन व समझ रहे थे तकनीकी सत्र में २५० लोगो ने भाग लिया।

इण्डिया फूड एक्सपो – २००४ के समापन एवं इण्डिया फूड एक्सपो– २००५ के अनावरनण हेतु माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश आचार्य विष्णु कान्तशास्त्री जी अशोक मार्ग स्थित बलरामपुर कम्पाउंड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे।

उन्होने कहा कि "इस प्रकार के आयोजनो से ग्रामीण भारत के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होने कहा कि मेरा अनुभव है कि मध्यम वर्ग से आये युवा उद्यमी ही बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर ऋण चुकाते है क्योंकि उनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नही होता।"

सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होने इस बात पर हर्ष व्यक्त किया उ०प्र० में पहली बार एक ऐसे उद्योग के विकास के लिये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जो सीधें तौर पर ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ हैं

समापन समारोह के पूर्व संगोष्ठी के चौथे व पॉचवे सत्र सम्पन्न हुए जिसमें(आई०आई०पी०) भारतीय पैकेजिंग संस्थान के श्री एन०सी० शाह ने कम लागत पर सुरक्षा पूर्वक खाद्य सामग्री के यातायात पर चर्चा की इसके उपरान्त सीआईपीईटी की श्रीमती सानिया अख्तर ने खाद्य प्रसंस्करण में प्लास्टिक के उपयोग विषय पर जानकारी दी।

आई टीआरसी के डा०वी०पी०शर्मा ने पैकेजिंग प्लास्टिक के सुरक्षित उपयोग पर चर्चा की, सीआईएसएच के डा० डी०के० टण्डन ने ताजे फल एवं सब्जियों के रखरखाव के बारे में बताया। एनटीपीसी के श्री अनिल कुमार ने कृषि उत्पादन में कोयले की राख की उपयोगिता पर चर्चा की।

सीएफटीआरआई के श्री आईसी शुक्ला ने खाद्य प्रसंस्करण कानूनो के बारे में बताया व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के श्री एम०के० सिंह ने लाईसेन्सिंग के बारे में बताया।

अन्त में दिल्ली से आये श्री विजय सरदाना ने क्वालिटी कन्ट्रोल पर चर्चा की। इसके पहले सत्र में सिडबी के श्री नम्मायाल ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता विषय पर चर्चा की गई। एचपीएमआई चण्डीगढ के श्री सतेन्द्र यादव ने उ०प्र० में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के पुनर्गठन पर चर्चा की वही यूपी डास्प के श्री आर०पी० सिंह ने रॉ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में बताया।

आयोजन के दौरान सबसे अच्छे और उपयोगी प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार भी वितरित किये गये। इस श्रंखला में कारगिल इण्डिया लि० को प्रथम पुरस्कार दिया गया। अमृतसर से आए गुरूनानक इंजीनियरिंग वर्क्स को द्वितीय पुरस्कार व बाल बाटिका शिक्षा प्रसार समिति कानपुर देहात को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। लखनऊ की महिला उद्यमी द्वारा संचालित जायका ग्रामोद्योग समिति को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।

आई०आई०ए० खाद्य प्रसंस्करण वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष श्री रजनीश सेठी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे सभी सहयोगी संस्थाओं, डेलीगेटस, विशेषज्ञो, प्रदर्शनकारियों व लखनऊ वासियों को धन्यवाद देते है जिन्होने इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया।

उन्होने सचिव खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० श्री अनिल स्वरूप को विशे। धन्यवाद देते हुए उन्हे आई०आई०ए० का फ्रेंड, फिलॉस्फर व गाईड बताया और कहा कि श्री स्वरूप ने सम्पर्ण आयोजनो को व्यक्तिगत तौर पर लिया हैं। □

INDIA FOOD EXPO 2004 PHOTO GALLERY

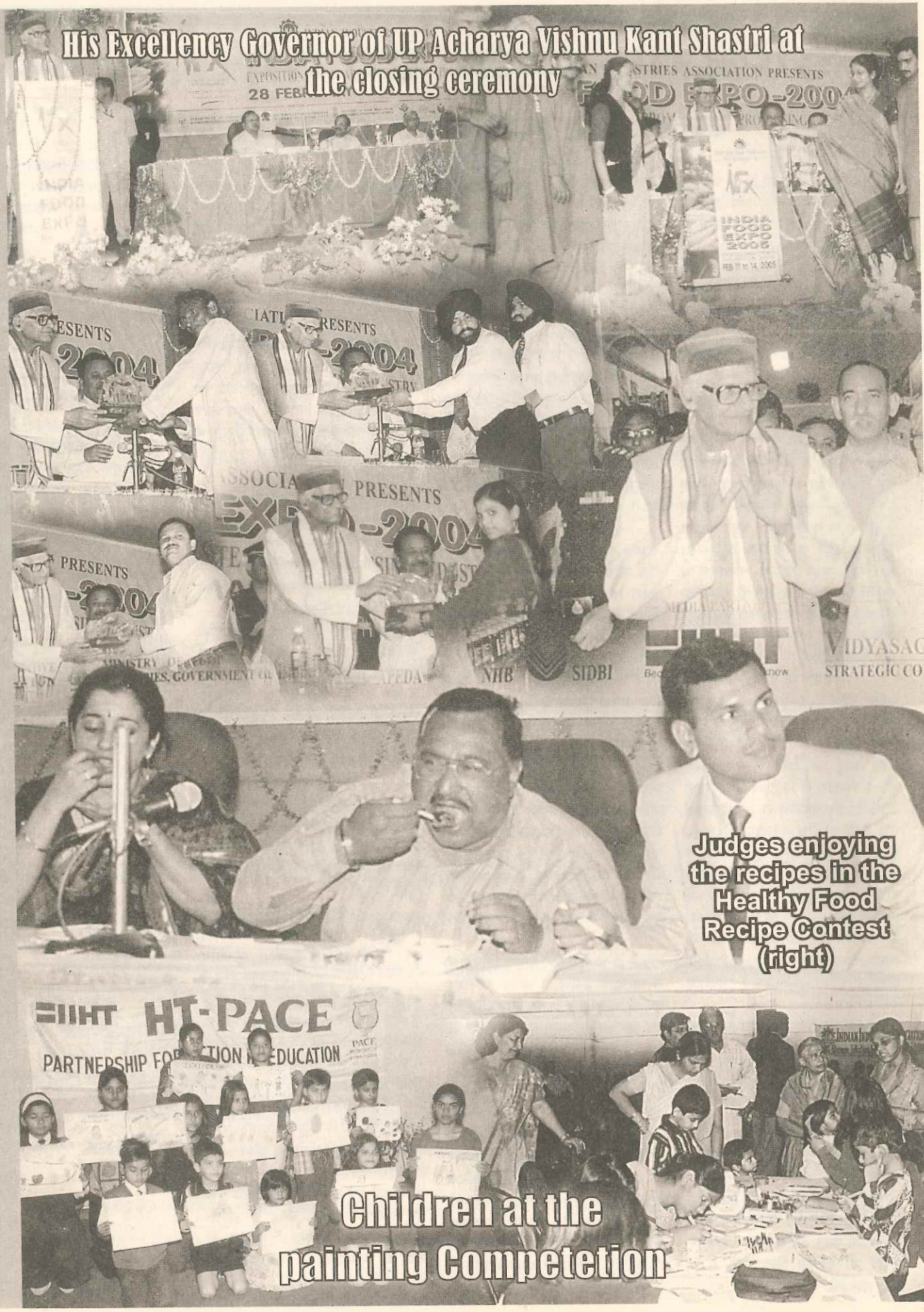

Focus Food Quality and Safety to ensure Profitability in Food Business

Excerpts from the presentation given by Shri Vijay Sardana on day -I of **India Food Expo 2004**

Food Trade: Growing Opportunities or Growing Concern

The growth rate of food production is faster than population growth rate. It means we are heading for food surplus economy worldwide. At the same time there are some problems related to food distribution in the areas where there is no purchasing power. In this scenario when demand is less than supply, Can we afford to ignore the consumers' bargaining power and ever increasing demand for quality and food safety? The increasing number of food consignments getting rejected in world market and new food safety legislations around the world are focusing on how to eliminate bad suppliers from the market. In this scenario how long can we continue to crib that we are a country of small and poor farmers and we cannot produce safe and quality food, so please accept whatever we produce? I doubt even the growers and processors will buy their own product if they have option.

World Trade in Agricultural Products, 2001	
Value $bn	**547**
Year	**Annual change %**
1980–85	–2
1985–90	9
1990–2001	3
1998	–5
1999	–3
2000	1
2001	–1
Share in world merchandise trade %	**9.1**
Share in world exports of primary products %	**40.9**

Source: WTO International Trade Statistics 2002, table IV.3, includes trade between EU members

Let us be clear, Food trade is not alone a trade in commodities rather it is trade in commodities which can have serious impact on public health. There is an old saying, **"You are what you eat".** In other words, bad food means bad health. No one wants to buy food product, if he is not sure about safety of the food product. Price is secondary in food business and Consumers compromise on quality only in extreme situations but this is not a sustainable model for any food business organizations. In food business, a reliable food safety system ensures sustainable profitability.

Food Hazards don't respect borders:

Evolution of Notifications 1999-2002 in EU					
Year	**Alerts**	**Information**	**Addition to Alerts**	**Addition to Information**	**Total**
1999	97	263	279	59	698
2000	133	340	253	98	824
2001	302	406	549	310	1567
2002	434	1092	1032	466	3024

Food borne disease is a major cause of concern worldwide and it takes a major toll on health worldwide. Millions of people fall ill and many of them die as a result of eating unsafe food. Due to the growing incidences of food borne illnesses, the Fifty-third World Health Assembly in May 2000, adopted a resolution calling upon the World Health Organization (WHO) and its Member States to recognize food safety as an essential public health function. The resolution also called on WHO to develop a Global Strategy for reducing the burden of food borne disease.

Why New Food Safety Laws are emerging?

The availability of safe food improves the health of people and is a basic human right. Safe food contributes to health and productivity and provides an effective platform for development and poverty alleviation. People are becoming increasingly concerned about the health risks posed by microbial pathogens and potentially hazardous chemicals in food. According to WHO and FAO studies, up to one-third of the populations of industrialized and developed countries are affected by food borne illness each year, and the problem is likely to be even more widespread in developing countries. The poor are the most susceptible to ill health. Food and waterborne diarrhoeal diseases, for example, are leading causes of illness and death in less developed countries, killing an estimated 2.2 million people annually, most of whom are children.

Due to globalization of trade, emerging trends in global food production, processing, distribution and preparation pose new challenges to food safety. Food grown in one country can now be transported and consumed halfway across the world. People demand a wider variety of foods than in the past; they want foods that are not in season and often eat away from home. Institutionalizing children in schools and childcare facilities and a growing number of elderly persons in hospitals and nursing homes means that food for many is prepared by a few and can therefore be the source of major foodborne disease outbreaks. Greater life expectancy and increasing numbers of immuno-compromised people mean a larger vulnerable population for whom unsafe food is often an even more serious threat.

continued on page 13

INDIA FOOD EXPO 2004 PHOTO GALLERY

Secretary Horticulture & Food Processing Government of UP Shri Anil Swaroop- The inspiration behind India Food Expo - 2004

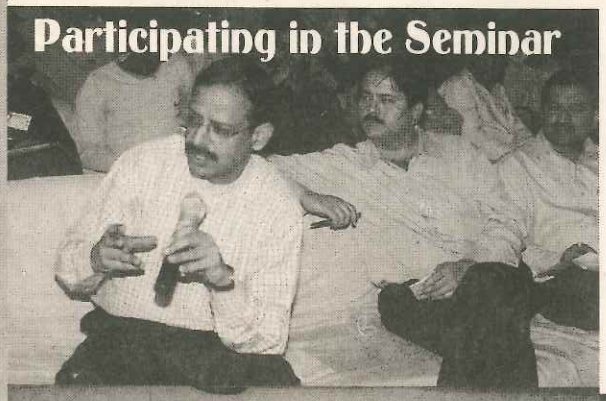

शाहजहाँपुर

दिनांक ३ फरवरी ०४ को आई०आई०ए० की एक बैठक होटल सत्यम में अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गर्ग की अध्यक्षता में प्रान्तीय सचिव श्री अशोक अग्रवाल की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

आई०आई०ए० द्वारा २० फरवरी ०४ को आयोजित किये जाने वाले उद्योग मेला –२००४ की रूपरेखा व विस्तृत तैयारियों पर था। सचिव अनिल गुप्ता ने बताया मेले का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन है।

मेला के संयोजक श्री प्रदीप गुप्ता ने बताया इसमें अर्धसरकारी या सरकारी विभाग जैसे यूपीएफसी, यूपीएसआईडीसी, एनआईएससी, डीआईसी, विभिन्न बैंक, लीड बैक, जनपद के उद्योगो के स्टाल व कुटीर लघु उद्योगो के स्टाल रहेंगे।

प्रान्तीय सचिव श्री अशोक अग्रवाल ने बताया चूकि यह जनपद कृषि क्षेत्र है इसलिए कृषि आधारित उद्योग का बहुत स्कोप है। उद्यमी श्री माधागोपाल अग्रवाल ने बताया कि यहाँ पर फूड ग्रेन के अलावा, आलू, गन्ना प्रमुख फसले है। अतः इस मेले में उद्योगों के विशेषज्ञ आलू या कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों के बारे में विस्तार से जानकारी देगे।

उद्यमी श्री आलोक महेश्वरी जो अभी हाल ही में विदेश यात्रा से लोटे है ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में कालीन का अच्छा व्यवसाय विदेशों में हो सकता है जरूरत है तो इस उद्योग का विकास करने की।

उद्यमी किशन अग्रवाल ने बताया कि इस मेले में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए उनके भी स्टाल होने चाहिए। श्री प्रेम तुली ने कहा कि जनपद में सिले कपड़े, बुटीक, आदि हस्तशिल्प, जरी, कारचोबी कढ़ाई आदि का भी काम होता है तथा उनकी

शेष पृष्ठ 15 पर

प्रिया गोल्ड

KRISHNA FOOD INDUSTRIES